VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 1447625

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : NEERAJ SONGARA

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
Hindi

तारीख
Date
26 / Aug / 2023

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre
Delhi-03
BHAI JOGA SINGH SCHOOL.

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
With suitable examples, discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

दबाव समूह अनौपचारिक संगठन का प्रकार है जो सरकारी तंत्र पर बाहर से दबाव बनाकर अपने समूह के हितों की पूर्ति का प्रयास करते है।

वर्तमान समय में पर्यावरणीय क्षेत्र में कई दबाव समूह सक्रिय है जिनमें वनशक्ति NGO, कन्सरवेशन इंडिया, वन अधिकार और ~~वन्य~~ वन-जीव जन्तु संरक्षण मोर्चा आदि प्रमुख है।

पर्यावरणीय नीतियों पर दबाव समूहों का प्रभाव:-

- सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाने में योगदान।
- अन्य विधिक सुधारों में इन पर्यावरणीय समूहों का इनपुट लिया जाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- नीतिगत प्रयासों की कमियों को उभारना करना।
- वन भूमि अधिकार अधि॰ निर्माण में योगदान।

परिणाम:–

- सरकारी प्रयासों का आंकलन
  - ↳ सामाजिक प्रभाव आंकलन
  - ↳ पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन
- विकास बनाम पर्यावरण में संतुलन।
- सुधारात्मक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य।

वर्तमान समय में न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय सक्रियता दिखाने के पीछे भी इन पर्यावरणीय समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

www.visionias.in

2. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक 'पेशे' के रूप में स्वीकार किया जाना, भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent acknowledgment of sex work as a 'profession' by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानवीय गरिमा की स्थापना करने के रूप में सेक्स वर्क को 'पेशे' के रूप में मानकर राज्य द्वारा इस कार्य में शामिल व्यक्तियों के निजी अधिकारों के संरक्षण हेतु दिशानिर्देश दिये गये हैं।

महत्व:-

- निजता के अधिकार की सुरक्षा। (गैर प्रशासनिक तंत्र द्वारा नैतिक पुलिसिंग पर रोक)
- स्वास्थ्य का अधिकार (बेहतर यौन स्वास्थ्य का अधिकार)
- समानता की गारंटी।
- जबरन, अवैध दैहिक पेशे पर नियंत्रण (पंजीकरण के फलस्वरूप)

- अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण।

समानता की दिशा में कदम :-

- पेशे की स्वतंत्रता। [19(1) g.]
- महिला- पुरुषों के मध्य समानता।

किंतु, समाजिक दृष्टिकोण व अन्य चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान :-

- सामाजिक रूढ़िवादिता।
- सामाजिक ~~कानून~~ परम्पराए व विधिक कानून में सामाजिक परम्पराए अधिक प्रबल।
- सामाजिक शुचिता का प्रश्न।

वर्तमान समय में SC का प्रयास एक बेहतर कदम में इस दिशा में सभी हितधारकों के व्यापक विमर्श की आवश्यकता है।

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the role played by District Legal Services Authorities (DLSAs) in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनु. 39(A) के तहत विधिक सेवा अधिकारों को प्रभावी रूप देने का प्रयास करने की बात कही गयी है।

इस संदर्भ में भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी है:-

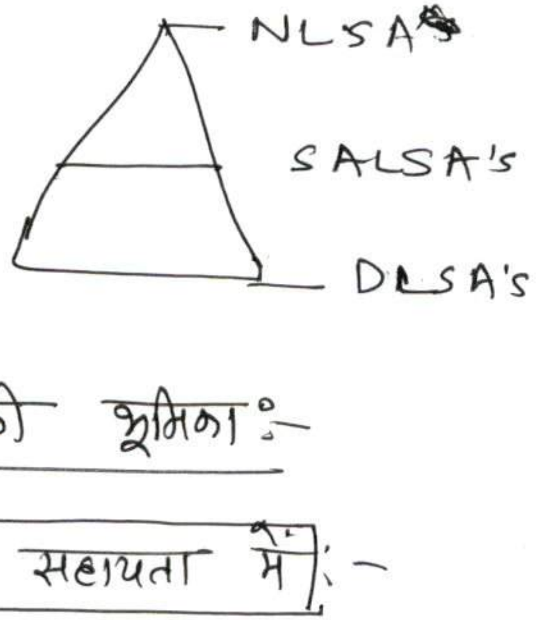

DLSA's की भूमिका:-

① कानूनी सहायता में:-

- वंचित वर्ग SC, STs, महिला ट्रांसजेंडर आदि को कानूनी सहायता (नि:शुल्क)
- अन्य मामलों में सलाह।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- बेहतर वकीलों द्वारा संरक्षण।
- राज्य के विरुद्ध भी वंचित वर्ग को सलाह।

(2) **कानूनी जागरूकता** — भारतीय न्याय प्रणाली का जिला स्तर पर प्रचार - प्रसार।

- संगोष्ठी का आयोजन।
- रिपोर्टों की प्रस्तुति।
- नुक्कड़ - नाटक।
- स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम।

विधि की त्रि स्तरीय व्यवस्था न्याय प्रणाली को सबसुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. "कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण, कॉलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"The collegium system has become a victim of its own success, with the concentration of power in the hands of a few, leading to questions about its legitimacy." Comment. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में तृतीय जजेस केस (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघवाद) के बाद वर्तमान कोलेजियम प्रणाली को वास्तविकता प्राप्त हुई है।

कोलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत SC के मुख्य न्यायाधीश व अन्य 4 वरिष्ठ SC न्यायाधीशों के कोलेजियम द्वारा नये न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को बाध्यकारी सलाह प्रदान की जाती है।

कोलेजियम प्रणाली के लाभ :-

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
- कार्यपालिका हस्तक्षेप में कमी।
- वरिष्ठता का सम्मान।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- कार्यपालिका से लोभ की गुंजाइश समाप्त फलत: न्यायिक निर्णयों में सत्यनिष्ठा बेहतर।

हानि:- • न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। (शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध)
- चेक एण्ड बैलेंस की कमी।
- पारदर्शिता में कमी।

★ कुछ लोगों के हाथों में शक्ति का संकेंद्रण :-
↳ CJI + 4 जजों की भूमिका।
- अन्य जजों की राय का महत्व नहीं।
- कार्यपालिका की वास्तविक समस्याओं को नजरदाज किया जाना।
- नियुक्ति पर गतिरोध।
- टकराव की स्थिति।

भारत में इस समस्या के समाधान हेतु आस्ट्रेलिया के तर्ज पर न्यायिक नियुक्ति आयोग को अपनाया जाना बेहतर रहेगा।

www.visionias.in

5. "सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"Civil services reforms must go beyond recruitment and standardised training to cope with the present day challenges." Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में सिविल सेवा प्रशासन की धमनियों के समान है जो सामाजिक सेवा के साथ राष्ट्र के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

वर्तमान ~~समय~~ की चुनौतियाँ :-

- तकनीकी स्तर में वृद्धि किंतु ~~सिविल~~ सेवा मानव विकास प्रबंधन कौशल में कमी।
- न्यायिक वादों में बढ़ोत्तरी। (कुल 5.2 cr)
  - ↳ तकनीकी क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता ताकि वाद संबंधी स्थिति उत्पन्न न हो।
- लोककल्याणकारी राज्य की बढ़ती आकांक्षाएं।
  - ↳ युवाआबादी
  - ↳ वृद्ध आबादी में बढ़ोत्तरी

~~चुनौतियाँ~~

सरकारी प्रयास :- iGOT ट्रेनिंग प्लेटफार्म

↳ ० आरम्भ फाउन्डेशन सिविल सेवा प्रोग्राम।

↳ ० CPGRAMS.

↳ ० लेटरल एंट्री

वर्तमान जटिल चुनौतियों के समाधान हेतु अन्य सुझाव :-

- लेटरल एंट्री को और विस्तार (होता कमेटी)
- तकनीकी कौशल हेतु मध्यकालिक ट्रेनिंग में सुधार (AI, ब्लॉकचेन आदि का व्यवहारिक ज्ञान)
- VRS सेवा का सटीक प्रयोग।
- निजी क्षेत्रों में प्रोबेशन कार्य की अनुमति (दक्षता में सुधार)

वर्तमान भारत को 2047 तक विकसित बनाने में ये सिविल सेवा सुधार लाभकारी ~~होंगे~~ रहेंगे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे परिणाम-आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Outcome-based finance models such as social impact bonds have the potential to truly catalyse change and deliver socio-economic impact at scale. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में UNDP के अनुसार सामाजिक प्रभाव बाण्ड्स के कई लाभकारी परिणामों के संभावना को एक रिपोर्ट में साझा किया गया है।

सामाजिक प्रभाव बाण्ड के प्रभाव -

- सामाजिक क्षेत्रों में निवेश में सुधार।

उदा.

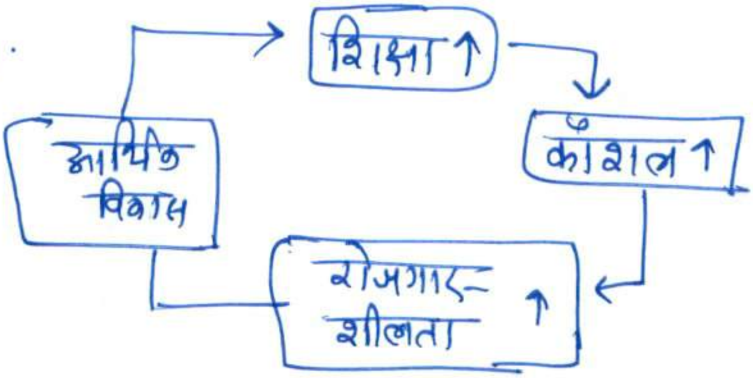

- महिलाओं के सशक्तीकरण में भूमिका।
  - ↳ सम्पूर्ण परिवार की पोषण सुरक्षा।

- राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि।
  - ↳ आधी आबादी के मुद्दे मुख्यधारा में शामिल होंगे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- समावेशी विकास में भूमिका।
  - ↳ गरीबी निवारण → राष्ट्र का वास्तविक लोकतांत्रीकरण
- सामाजिक न्याय की स्थापना।
  - ↳ वंचितों (SC, ST, OBC's के महिला, ट्रांसजेंडर) के सामाजिक-राजनीतिक स्थिति में सुधार।
- विभिन्न सामाजिक संकेतकों में सुधार के क्रम में भारत में बहुआयामी गरीबी में कमी।
- भारत के संभवित मानव पूंजी को कौशलीकृत कर राज्य की आर्थिक सामाजिक दशा में सुधार।

वर्तमान समय में ये सामाजिक प्रभाव बांड अपनी शैशवावस्था में इसे और विस्तारित कर लाभों को सर्वव्यापक बनाने की आवश्यकता है।

7. प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The wide gap between the number of females graduating every year and those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संयुक्त राष्ट्र विमेन इन सांइस रिपोर्ट के अनुसार भारत में STEM क्षेत्र में सर्वाधिक महिला ग्रेजुएट हो रही है तो वही नियुक्ति के क्रम में भारत 19 वें स्थान पर है।

यह स्थिति एक विचित्र विरोधाभास को दर्शाती है जिसके निम्न कारण विद्यमान है:-

① सामाजिक दबाव

↳ पितृसत्तात्मक मानसिकता।

↳ दोहरा दबाव → शिक्षा
↳ गृहकार्य का भार

↳ ग्लास सिलिंग

↳ ग्लास क्लिफ

↳ प्रजनन अधिकारों को मान्यता में कमी

फलत: रोजगारशीलता में कमी व दबावों के चलते नौकरी छोड़ना।

② आर्थिक दबाव → श्रम मूल्यों में कमी।
↳ श्रम में भेदभाव

③ राजनीतिक भागीदारी में कमी अंतः आर्थिक नीतियों में महिला समर्थक नीतियों की उपेक्षा। (आरक्षण, कार्यक्षेत्र में सुधार के प्रयास)

सुधार के प्रयास ◦ राष्ट्रीय शिक्षा नीति
↳ समावेशिता पर बल।
↳ POSH अधिनियम।
↳ मातृत्व सुरक्षा कानून।
↳ क्रेच फैसिलिटी (श्रम संहिता में सुधार)
↳ किरण योजना

उपरोक्त प्रयासों को ही और प्रभावी सर्वव्यापक रूप से लागू कर हम "महिलाओं के नेतृत्व में विकास" की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. भारत में सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिए एक अद्यतित और कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) अनिवार्य है। देश में CRS प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम के आलोक में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

An up to date and functional Civil Registration System (CRS) is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of the recent move of the Central government in revamping the CRS system in the country. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नयी, आधुनिक प्रक्रिया का पालन करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया है।

इसके माध्यम से जन्म प्रमाण व मृत्यु प्रमाण डाटा को रियल टाइम में अपडेट करते हुए आधार डाटा से जोड़ने का दायित्व सौंपा गया है।

आवश्यकता क्यों?

- बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यक।
- नीति निर्माण व क्रियांवयन में सहायक।
- लक्षितकरण में बेहतर।
- संसाधनों का उचित बटवारा।
- आपदा के संदर्भ में बेहतर निवारक और प्रक्रियात्मक उपाय।

www.visionias.in

• अंतर राज्य व अंतर देशीय प्रवास डाटा का विश्लेषण।
• सार्वजनिक सेवाओं का आंकलन।

हालिया प्रयास:-

• जनगणना हेतु e- उपकरणों का प्रयोग।
• आधार डाटा लिंकेज।
• जन्म - मृत्यु डाटा का रियल टाइम अपडेशन। (राज्यों को निदेश)
• डाटा फीडिंग तंत्र में एकरूपता।
• डाटा के सेट में सुधार
  ↳ (बायोमैट्रिक डाटा)

भारत में वृहद आबादी के प्रवास, आर्थिक - सामाजिक स्थिति का वास्तविक आंकलन कर ही नीतियों को लक्षित किया जाना संभव है इस दिशा में सुधार हेतु CRG में किये सुधार लाभकारी होंगे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित होना है तो इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन-से होंगे? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the key areas of reform if the International Monetary Fund (IMF) has to align with the current economic realities? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत की विदेश नीति की ~~प्राथमिकता~~ प्राथमिकता में बहुराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार एक प्रमुख लक्ष्य है।

इसके अंतर्गत IMF में भी व्यापक सुधार की बात भारत द्वारा समय समय पर की गयी है।

IMF की वर्तमान समस्याएं

↳ वास्तविक आर्थिक सुधार में प्रकृति सफल नहीं।

- विकसित देशों का प्रभुत्व (यूरोपीय अध्यक्ष)
- ASEAN, BRICS, देशों की भागीदारी में कमी (निर्णय लेने में)
- आर्थिक संकटों को रोकने में विफल।
  ↳ 2008 वैश्विक मंदी
  ↳ वर्तमान विकसित राष्ट्रों द्वारा तट्स्थ नीति के विश्व पर प्रभाव।

सुधार के प्रमुख स्रोत :-

- भागीदारी में सुधार -
  - ↳ दक्षिणी राष्ट्रों की भागीदारी में सुधार।
- ऋण देने में पारदर्शिता।
  - ↳ विकासशील व LDCs देशों की ऋण संधारणीयता में सुधार।
- भारत को SDR बास्केट में डाला जाये। (वृहद आबादी + 5वी बड़ी अर्थव्यवस्था)
- SDR को रिजर्व हैंस टैन्च में सुधार।
- इनवॉयसिंग में सुधार।
- विकसित देशों के प्रभुत्व में कमी।

वर्तमान बदलती वैश्विक स्थिति के अनुरूप बहुपक्षीय संस्थाओं को बहुलतावादी व लोकतांत्रिक बनाना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. हाल के वर्षों में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भू-राजनीति के दायरे से आगे निकलकर भू-अर्थशास्त्र के आयाम तक पहुंच गए हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
In recent years, India's relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to expanse of geoeconomics. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत की पश्चिम एशियाई विदेश नीति सर्वदिशात्मक (Poly directional) है। इसके द्वारा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के साथ वैश्विक व्यापार को विविधता प्रदान कर रहा है।

पश्चिम एशिया में भारत के हित :

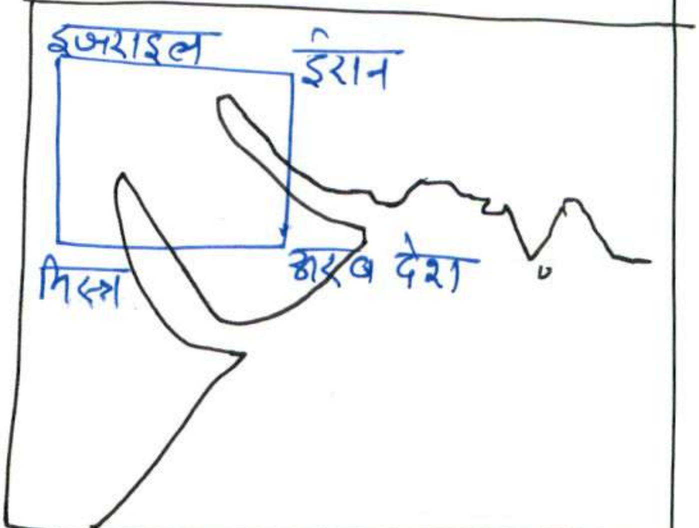

① ईरान

↳ चाबाहार बंदरगाह सामरिक व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण

↳ INSTC के माध्यम से केंद्रिय एशिया (Central Asia) में पहुंच।

② अरब देश (UAE मुख्यत:)

↳ ऊर्जा आवश्यकता की 60% प्राप्ति

↳ अर्थव्यवस्था की चालक।

- विप्रेषण की प्राप्ति।
- सोवेरन फण्ड द्वारा भारत में निवेश।
- IND - UAE CEPA के माध्यम से व्यापार में तेजी।

इज़राइल

- I2U2 समझौते के फलस्वरूप तकनीक व कृषि में बेहतर लाभ की संभावना।
- व्यापार विविधीकरण के प्रयास।

मिस्र

- भारत मिस्र व्यापार में 75% की वृद्धि ($7.2B)
- भारत के लिए प्रमुख गेटवे।

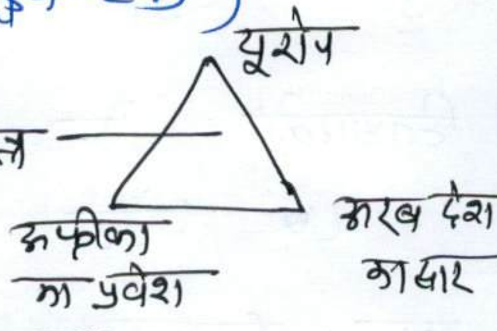

इस प्रकार पश्चिम एशिया का क्षेत्र बदलती भू-राजनीति के साथ, बदलते भू-अर्थशास्त्र का केंद्र भी बनता जा रहा है जहाँ भारत दोनों क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The role of the Competition Commission of India (CCI) is significant in furthering healthy competitiveness aimed at inspiring stakeholders to innovate and augment effectiveness. Comment. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में CCI के द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों, एकाधिकारवादी प्रैक्टिस को रोकने की दिशा में प्रतिबंधात्मक व निवारक उपाय किये जाते हैं।

महत्व :-

- प्रतिस्पर्धा का लाभ आम जन तक पहुंचाने हेतु।
- हितधारकों के नवाचारों को संरक्षण।
  - ↳ पेटेंट अधिकार, ट्रेड सिक्रेट का संरक्षण।
- एकाधिकारवादी पद्धतियों से बाजार का संरक्षण।
- घरेलु, लघु व मध्यम उद्योगों को संरक्षण।

लाभ :-

- भारत में विदेशी निवेश में सुधार करने में सहायक।
  - ↳ कॉपीराइट के व्यवस्था को प्रभावी बनाने में भूमिका।
- लोगों को लाभ।
- LPG के लाभ को बढ़ावा देते हुए, विदेशी फर्मों की अनुचित गतिविधियों पर संरक्षण।
- रिटेल बाज़ार का संरक्षण।

मुद्दे :-

- निर्णय में देरी।
- टेलीकाम सेक्टर में एकाधिकारवादी प्रक्रिया रोकने में विफल (66% भागीदारी 2 कम्पनियों की)
- लालफिताशाही।
- नवाचार प्रतिस्पर्धा पर अंकुश।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सुधार -

- जागरूकता प्रसार।
- तकनीकी दक्षता।
- मानव विकास व प्रबंधन में सुधार।

भारत में $100B वैश्विक निवेश प्रतिवर्ष प्राप्ति हेतु CCI की प्रभावशीलता को और बेहतर करने की आवश्यकता है।

12. "पेड न्यूज का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है।" भारत में पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
"The menace of paid news often rears its ugly head during elections." Discuss the need for making paid news an electoral offence in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पेड न्यूज का आशय छद्म विज्ञापन से लिया जा सकता है जिसका प्रयोग किसी राजनेता द्वारा अपने पक्ष या विपक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है।

चुनावों में पेड न्यूज के प्रभाव :-

- राजनीतिक शुचिता में कमी।
- लेवल प्लेयिंग फिल्ड का न होना।
- राजनीतिक लोकतंत्र के विरुद्ध।
- जनता को गलत जानकारी का प्रसार कर उनके मत को प्रभावित करना। (सूचित निर्णय के विरुद्ध)
- भ्रष्टाचार में वृद्धि।
- जनभागीदारी पर प्रभाव।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- राजनीतिक तंत्र में विश्वास में कमी।
- अच्छे, चरित्रवान लोगों का राजनीति से दूरी।

समाज पर प्रभाव:-

- वास्तविक मुद्दों (गरीबी, अशिक्षा, समानता, नारी सशक्तीकरण, समावेशी विकास) से ध्यान हटना।

देश पर प्रभाव:-

- राजनीति भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता।
- राजनीतिक आरोपण से सार्वजनिक मुद्दों पर सहमति का अभाव

चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता:-

- पेड न्यूज में कमी आयेगी।
- राजनीतिक शुचिता की स्थापना।
- लोगों को सूचित मत वास्तविकता में प्राप्त होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- सूचना का लोकतांत्रीकरण।
- मीडिया के ~~प्रचार~~ भ्रष्ट आचरण पर अंकुश।
- राजनीति ~~के~~ अपराधीकरण में कमी।

लागू करने में समस्याएँ-

- चुनाव आयोग की शक्तियों में विस्तार आवश्यक (पंजीकरण रद्द करने की शक्ति)
- कार्यभार में बढ़ोत्तरी (मानव संसाधन की कमी) → स्वतंत्र काडर की आवश्यकता → स्वतंत्र सचिवालय

अतः उपरोक्त व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर पेड ~~न्यूज़~~ न्यूज पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

13. भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, न्यायालयों द्वारा उद्धृत 'अनिवार्यता के सिद्धांत' पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Discuss the 'Doctrine of Essentiality' referred to by the courts in the context of religious practices in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में कर्नाटक हिजाब विवाद में 'अनिवार्यता का सिद्धांत' ~~प्र~~ पर चर्चा शुरू हुई।

सर्वप्रथम ~~शिरूर~~ शिरूर मठ वाद में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था।

इसके तहत किसी भी धर्म के अनिवार्य भाग के अतिरिक्त किसी भी कार्य, प्रथा, मान्यता आदि को मूल अधिकार (Art-25-26) के अंतर्गत संरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

इस्माइल फारूकी वाद में मस्जिद को इस्लाम का अनिवार्य नहीं ~~भाग~~ माना गया फलत: सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक

अधिकारों के युक्तियुक्त निर्बंधन को उचित माना गया।

हालांकि कई विधि शास्त्रियों द्वारा "अनिवार्यता के सिद्धांत" की निम्न बिंदुओं पर आलोचना की जाती है:-

1. कई विशेषज्ञ यह मानते है कि यह सिद्धांत के द्वारा न्यायपालिका ने अपने भार को ~~अधिक~~ आवश्यक रूप से बढ़ा लिया है।
(वर्तमान में 5.2 करोड़ वाद लंबित)

2. सामाजिक सुधार का कार्य कार्यपालिका व विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए।
(शक्ति संतुलन के विरुद्ध)
+ न्यायिक अतिरेक

3. भारत के विविधतामूलक समाज में न केवल धर्मों में अपितु सम्प्रदाय व पंथों में भी अलग अलग

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

मान्यता स्थापित है अपितु 'अनिवार्यता के सिद्धांत' व्यवहारिक रूप से लागू होना कठिन प्रतीत होता है।

अनिवार्यता के सिद्धांत के सकारात्मक प्रयोग:-

→ शाहबानो वाद में "तलाक प्रथा में रूढ़िगत मान्यताओं को धार्मिक कार्यों से अलग माना गया।

→ सबरीमाला वाद में समानता को बढ़ावा देने के क्रम में।

→ शायरा बानो वाद (तीन तलाक) पर रोक।

→ मदरसों में शिक्षा सुधार हेतु राज्य के हस्तक्षेप को उचित माना। (बंगाल राज्य)

इस प्रकार इस सिद्धांत के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए SC द्वारा इसका तार्किक व अल्प प्रयोग करना उचित प्रतीत होता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

As per the recently released report of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), there is an urgent need to limit the size of the government in India. Do you agree? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रयास किया गया है।

अब लोकसभा के संसद के 10% सीमा तक ही मंत्रियों मंत्रिपरिषद विस्तारित की जा सकती है।

बड़ी मंत्रिपरिषद की व्यवहारिकता :-

लाभ :

- बेहतर प्रतिनिधित्व।
- नेतृत्व विकास
- क्षेत्रीय आकांक्षा की पूर्ति
- बेहतर सलाहकारी तंत्र

हानि :-

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

1. सरकारी राजस्व पर दबाव।
2. समन्वय का अभाव। (बहुदलीय प्रणाली)
3. एकीकरण में कमी; आवश्यकता

परिवहन मंत्रालय — रेलवे मंत्रालय — जल परिवहन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय → एकीकरण

4. निर्णय लेने में देरी।
5. राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि। (मंत्री बनाने का लालच दिया जाना)
6. स्थायी कार्यपालिका पर खर्च में बढ़ोत्तरी (प्रत्येक मंत्रालय का पृथक सचिव) → पृथक कार्यालय।
7. प्रयासों का दोहराव।

8. EAC-PM के सुझाव :-

- संख्या को 33% तक करने का सुझाव। (33 से 40% तक)

• परिवहन मंत्रालय में (रेल, सड़क, वायुयान क्षेत्रों को शामिल करना)

• दोहराव में कमी हेतु लाभकारी रहेगा।

• राज्यों के मंत्रिपरिषद में कमी राजकोषीय स्थिति के साथ राजनीतिक भ्रष्ट आचरण में कमी लायेगी।

मत

• सर्वप्रथम व्यापक राजनीतिक विमर्श आवश्यक है।

• संविधान संशोधन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य अत। क्षेत्रीय परिषद में व्यवहारिक, क्रमिक उपायों पर कार्य किया जाये।

सर्वप्रथम मंत्रालयों को एकीकृत कर क्षेत्रक विशिष्ट बनाते हुए गतिशक्ति मानीटरिंग सिस्टम के द्वारा प्रथम पंक्ति के सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता अधिक प्रासंगिक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना की कल्पना भारत में उच्चतर शिक्षा के 'विश्व स्तरीय' केंद्र विकसित करने के लिए की गई थी, लेकिन छह साल बाद भी, यह अभी तक गेम चेंजर नहीं बन पाई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The Institutions of Eminence (IoE) scheme was conceived to develop 'world-class' centres of higher education in India but six years later, it is yet to become the game changer it was intended to be. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

IoE योजना के द्वारा भारत में सरकार द्वारा सरकारी व निजी क्षेत्रकों में क्षेत्र विशिष्ट, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हुई विश्व स्तरीय संस्थानों के स्थापना का लक्ष्य रखा गया था।

IoE योजना के अंतर्गत प्रयास:-

- शिक्षण पद्धति में सुधार।
- शिक्षा प्रशासन में रणनीतिक स्वायत्तता।
- निजी- सार्वजनिक भागीदारी।
- भारत को ज्ञान राजधानी में बदलना।
- वित्तीय फंडिंग में सुधार।

किंतु, प्रभावी आपेक्षित लाभ में कमी

- QS रैंकिंग में स्थिति में सुधार नहीं (शीर्ष 200 में कोई संस्थान नहीं)
- निजी क्षेत्र की भागीदारी निम्न।
- उद्योग- शिक्षा जुड़ाव में कमी। (इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार केवल 49% ग्रेजुएट नौकरी के आपेक्षित कौशल रखते हैं)
- वित्तीय स्वायत्तता में कमी।
- संसाधनों में कमी।
- केंद्र राज्य संबंध
  - भाषा
  - भूमि अधिग्रहण

  ] संबंधी विवाद।

सुधार के अन्य प्रयास:-

- विदेशी संस्थानों को पारस्परिकता के अनुरूप भारत में संस्थान खोलने की अनुमति।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- 9 UAE में IIT की स्थापना।
- निजी क्षेत्रकों को स्वायत्तता में वृद्धि।
- NRF की स्थापना।

अन्य सुधार

- शिक्षा व्यय में सुधार (6% राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) (वर्तमान 2.1%)
- केंद्र राज्य सहयोग (भाषायी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान)
- रणनीतिक प्रयासों में तेजी लायी जाये।

भारत की युवा आबादी को शैक्षणिक व कौशल से युक्त कर ~~आबादी~~ भारत में उच्च शिक्षा में सुधार करते हुए भारत को ज्ञान राजधानी बनाने को साकारित करने के प्रयास में IoE योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अपेक्षित है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

16. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) नवोन्मेषी और सुविधाजनक सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति देता है, समावेशन या पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा रियल-टाइम डेटा की मदद से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Digital Public Infrastructure (DPI) allows for innovative and convenient public services, help overcome inclusion or accessibility barriers, and increase transparency and accountability with real-time data. Discuss with examples. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

DPI से आशय सार्वजनिक गैर-विभाजनकारी अवसंरचना से है जो सभी के लिए, सभी जगह, बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होती है।

आर्थिक सर्वे में DPI के उदाहरण के रूप में निम्न तकनीकों को भारत में समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

① जेम ट्रिनिटी (जन धन-आधार मोबाइल)
↳ DBT
↳ वित्तीय लाभ

② UPI
↳ सूक्ष्म स्तर पर वित्तीय क्षेत्र की पहुंच

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

③ COWIN. पोर्टल व राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

↳ सार्वजनिक ~~स्वा~~ स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण
↳ (अस्ताना डिक्लेरेशन के अनुरूप)
↳ SDG-4 की प्राप्ति

DPI के लाभ

① समावेशन में सुधार

↳ समावेशीकरण व बहिष्करण त्रुटि में कमी। (आधार डाटा)

② पहुंच संबंधी बाधा का समाधान

↳ जन धन आधार ~~लिंकेज~~ लिंकेज (PM-किसान का लाभ सभी को)

③ ↳ DPI द्वारा ONORC को साकारित कर पहुंच की बाधा का समाधान

रियल-टाइम डेटा-

- इंडिया स्टैक व एग्री स्टैक के माध्यम से योजना व लाभार्थियों की बेहतर निगरानी।
- नीतिआयोग - दर्पण पोर्टल

पारदर्शिता व जवाबदेहिता में सुधार

- सटीक लाभार्थी पहचान से राजस्व की बचत।
(वित्तमंत्री द्वारा कहा गया कि अब तक लगभग ₹ 2T की बचत)
- प्रशासन का दायित्व तय किया गया।
↳ CPGRAMS

DPI द्वारा भारत के आर्थिक विकास राजनीतिक सामाजिक विकास को समावेशी बनाने की क्षमता निहित है डिजिटल साक्षरता में सुधार से इसके लाभों में उत्तरोत्तर और वृद्धि होगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. कानून के अलावा, भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार' की पूर्ण प्राप्ति हेतु सामाजिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Besides legislation, the full realisation of the 'right to health for all' in India demands plugging of social, financial, and infrastructural gaps. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंधुआ मजदूरी संघ बनाम भारत संघ वाद में स्वास्थ्य के अधिकार को अनु-21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण माना है।

हाल ही में इस दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा विधिक प्रयास भी किया गया।

स्वास्थ्य के अधिकार के निहितार्थ :-

- सभी को सभी जगह, बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य का अधिकार।
- इसके अंतर्गत राज्य द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य व्यय को वहन किया जायेगा।
- स्वास्थ्य प्राप्ति को अधिकार रूप में मान्यता

जिसका उल्लंघन ~~दण्डित~~ दण्डनीय होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्वास्थ्य के अधिकार प्राप्ति में बाधक:-

सामाजिक
- शैक्षिक अधिकारों में कमी।
- जागरूकता में कमी।
- स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी।
- रूढ़ीवादिता (NFHS-4 2011 में 53% गर्भपात ही पंजीकृत डाक्टरों द्वारा किये गये।
- पीढ़ीगत गरीबी फलतः दीर्घकालिक स्वास्थ्य परेशानियां अधिक।

वित्तीय
- सरकारी व्यय में कमी लगभग 2.9%। (बल्कि, आवश्यकता 6%)
- सरकारी डाक्टरों की कमी (1 डाक्टर पर लगभग 1700 मरीज) (आदर्श स्थिति 1:1000 WHO)
- राज्यों की आर्थिक स्थिति में कमजोरी

बुनियादी ढांचा:

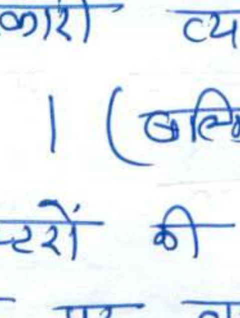

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
↳ 25 हजार केंद्रों में 9000 पद खाली

द्वितीयक स्वास्थ्य प्रणाली पर भार अधिक

तृतीय क्षेत्रक की सीमित पहुंच

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

सुधार के प्रयास :-

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।

OOPE ↓

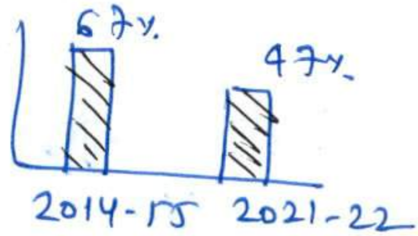

- आयुष्मान योजना।
- जेनेरिक दवाओं की पहुँच में वृद्धि।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डिजिटल संस्करण (e- संजीवनी)
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन।

इन नीतिगत सुधारों को बेहतर करते हुए वित्तीय सुरक्षा के उपायों की ओर आगे बढ़ना चाहिए साथ ही राजस्थान के वित्तीय प्रयासों का आंकलन करते हुए इसका क्रमिक विकास भी प्रभावी साबित होगा।

8. विधायी समर्थन के बावजूद 'थर्ड जेंडर' को अभी तक भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The 'third gender' has not yet been engendered in the Indian society despite legislative nudge. Analyse. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

~~नवतेज जौहर वाद में~~

~~समलैंगिक अधिकारों के~~

नालसा बनाम भारत संघ वाद में 'थर्ड जेंडर' को पहचान का सार्वभौमिक अधिकार दिया गया व SC द्वारा इस दिशा में विधिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।

सरकार के प्रयास:-

- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया।
- पहचान के अधिकार को मान्यता।
- थर्ड जेंडर के शैक्षणिक, विधिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता।

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- पुनर्वास ~~की~~ के नीतिगत प्रयास।
- राष्ट्रीय थर्ड जेंडर विकास बोर्ड की स्थापना।
- राज्यों को निर्देश।

प्रयासों के बावजूद स्थिति कमजोर :-

- समाज में मान्यता का अभाव।
  (ट्रांसजेंडर ~~~~. 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 4 लाख)
  (किंतु राजनीतिक अधिकार केवल 40 हजार लोगों को)
- भेदभाव का शिकार।
  (NALSA वाद में आरक्षण प्रावधान को विधिक रूप नहीं दिया गया)
- ~~हिंसा~~ समान हिंसा हेतु अलग अलग दण्ड।
  (महिला के विरुद्ध हिंसा पर अधिक दण्ड)
- डाटा का अभाव (मानव अधिकार आयोग ~~~~ के अनुसार देश में 40 से 60 लाख ट्रांसजेंडर)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- शैक्षणिक अधिकारों में कमी (पहुंच का अभाव)
- स्वास्थ्य का अधिकार नही
- पहचान हेतु जिला कलेक्टर की मान्यता जरूरी (आवेदन वापस होने पर अपील अधिकारों में अस्पष्टता।
- परिवार द्वारा शोषण।
  ↳ मानसिक विकार में वृद्धि।

सुधार के प्रयास:

- केरल, कर्नाटक द्वारा शैक्षणिक आरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आये।
- SHG के द्वारा सशक्तीकरण के प्रयास किये जाये (केरल - कुटुम्ब श्री)
- सामाजिक संवेदीकरण को बढ़ावा (लैंगिक संवेदनशीलता को शाला स्तर पर शामिल करने के प्रयास करें।

भारत में वर्षों से पीड़ित दमित यह वर्ग का सामाजिक आर्थिक सुधार करना हमारा नैतिक दायित्व है जिसकी पूर्ति हेतु उपरोक्त सुझाव लाभकारी होंगे।

19. अन्य कारकों के अलावा, चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectations from the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

हाल में सम्पन्न SCO बैठक में अंतिम वक्तव्य पर एकरूपता न बन पाना समूह में आपसी सहमति के अभाव को दर्शाता है।

भारत के लिए SCO का महत्व:-

- सेन्ट्रल एशिया से संबंधों में सुधार भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु आवश्यक।
- अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सामरिक गहराई का ताजिकिस्तान में भारत की उपस्थिति से प्रतिसंतुलित करना। (फारखोर एयरबेस का वायुसेना द्वारा प्रयोग)
- बहुपक्षीय संबंधों से विदेशी व्यापार को विविधीकृत बनाना।
- संयुक्त राष्ट्र में सहयोग।

किंतु, अपेक्षित लाभ में कमी:-

- चीन द्वारा भारतीय प्रस्तावों में व्यवधान उत्पन्न करना।
- क्षेत्रीय जुड़ाव में कमी (सेंट्रल एशिया से द्विपक्षीय व्यापार केवल $2B)
- भारत- रूस संबंधों में ~~अ~~ अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव।

प्रमुख कारक:— पाकिस्तान व चीन से संबंधों में गिरावट:-

- पाकिस्तान - चीन - व रूस का बनता त्रिगुट भारत की नयी संभावना तलाशने पर मजबूर करता है।
- चीन द्वारा ~~BB~~ BRI का विस्तार भारत की सेन्ट्रल एशिया में पहुंच को सीमित करता है।
- RATS का प्रभावी प्रयोग न कर पाने की विफलता।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- नयी शामिल देशों पर चीन का प्रभाव अधिक।
- समुद्र में बढ़ता चीनी प्रभुत्व भारत के क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध।

अन्य कारक - • आपसी व्यापार में कमी।
- पीपुल -टू पीपुल कनेक्ट में कमी।
- जुड़ाव में कमी INSTC पर धीमी गति।
- अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव।

SCO का प्रभावी प्रयोग भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के विविधीकरण व भारत की विस्तारित पड़ोस की नीति के अनुरूप है अतः इस क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु सक्रियता को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

0. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर हाल ही में संपन्न पहल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी साझेदारी में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का वादा करती है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The recently concluded initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) between the United States and India promises a long overdue transformation of their partnership in the field of technology. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत और अमेरिका सामरिक साझेदार है जिनके मध्य 4 प्रमुख रक्षा समझौते के बाद iCET प्रमुख समझौता है जिसके बहुआयामी लाभ होंगे।

iCET के लाभ:

- रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आसान बनायेगा।

  हाल ही में LCA तेजस MK2 हेतु सम्पन्न GE F 414 इंजन की प्रौद्योगिकी साझा करना इसका उदाहरण है।

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में भागीदारी। (चीन पर निर्भरता में कमी)
- साथ ही इसके भारत भारत को MSP (मिनिरल सप्लाई पार्टनरशिप) में भी शामिल किया जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
- iCET के आ। पहल देशों में रिसर्च के स्तर पर सहयोग होगा।
- आर्टेमिस एकार्ड में भागीदारी के लाभ अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण।
  - ↳ गगनयान मिशन
  - ↳ ISS पर भारतीय एयरोनॉट की उपस्थिति संभव।
- NRF व अमेरिकी थिंक टैंक में सहयोग।

अन्य मुद्दे:-

- अमेरिका द्वारा बार बार स्थितिजन्य परिवर्तन।
  - ↳ AUKUS की स्थापना।
  - ↳ पाकिस्तान को सैन्य सहायता।
- व्यापार नीतियों में अनिश्चितता। (व्यापार युद्ध)

हाल का सम्पन्न समझौता तकनीकी क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। साथ ही यह संबंधों को बहुआयामी बनायेगा इसके चलते भारत ड्रोन तकनीक, AI. में भी प्रभावी बढ़त बना सकेगा। साथ ही यह समझौता SCR± व चीन +1 रणनीति के अनुरूप है।

www.visionias.in

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK